THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): (a) to (c). Housing is a State subject and all Housing Schemes are formulated and implemented by the State Governments. However, references are received from time to time by the Central Government and the Housing and Urban Development Corporation from the States and their agencies including the Gujarat Housing Board. In the absence of the necessary details it is not possible to identify the correspondence that has passed or the visits that may have been made.

(d) and (e). During the period 1-1-82 to 31-1-83, HUDCO has sanctioned 15 projects of the Gujarat Housing Board with project cost of Rs. 11.03 crores and HUDCO's loan commitment of Rs. 7.99 crores.

खाद्यान्न के रक्षित भण्डार में कमी

*5 श्री चन्द्रपाल शैलानी :
श्री गुलाम रसल कोचक :

क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न के रक्षित भण्डार में कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के रक्षित भण्डारों में सदैव कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध रहना चाहिए;

(घ) भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के रक्षित भण्डारों में इस समय कितना खाद्यान्न है; और

(ङ) यदि इसमें कमी हो गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) सरकारी एजेंसियों के पास 1-1-1983 को खाद्यान्नों का कुल स्टाक लगभग 126.8 लाख मीटरी टन था जबकि 1-1-1982 को यह स्टाक 115.0 लाख मीटरी टन था। अतः 1982 के दौरान स्टाक की स्थिति में मामली सुधार हुआ है।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार, सरकारी एजेंसियों के पास विभिन्न तारीखों को 155 से 208 लाख मीटरी टन के बीच खाद्यान्नों का स्टाक होना चाहिए जिसमें 120 लाख मीटरी टन बफर स्टाक, साथ में 35 से 88 लाख मीटरी टन के बीच परिचालन स्टाक शामिल है।

(घ) सरकारी एजेंसियों के पास 1-1-1983 को खाद्यान्नों का कुल स्टाक 126.8 लाख मीटरी टन था।

(ङ) स्टाक के अपेक्षित स्तर में कमी मुख्यतया सूखा वर्ष 1979-80 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की भारी निकासी होने के कारण हुई है।

Measures to Curb Rise in Urban Land Prices

*6. SHRI K. MALLANNA:
SHRI UTTAMRAO PATIL:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the Central Government have suggested to the States Governments some measures to curb the unwarranted rise in the price of urban land as a part of the overall urban land policy to be devised by them to regulate its use; and